भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1551

09.02.2026 को उत्तर के लिए

तमिलनाडु की जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्ययोजना

1551. सुश्री एस. जोतिमणि :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जैसे बढ़ते तापमान, अनियमित मानसून, विषम मौसम की घटनाएं और समुद्र स्तर में वृद्धि के संबंध में कोई क्षेत्र-विशिष्ट आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) इन प्रभावों का शमन करने और तत्संबंधी अनुकूलन करने के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीसीसी) और जलवायु परिवर्तन संबंधी तमिलनाडु राज्य कार्ययोजना (टीएनएसएपीसीसी) के तहत क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने जलवायु-अनुकूल कृषि, जल संसाधन प्रबंधन और तटीय संरक्षण उपायों को लागू करने के लिए तमिलनाडु को वित्तीय या तकनीकी सहायता प्रदान की है;

(घ) क्या तमिलनाडु के किसी जिले की जलवायु-संवेदनशील या जलवायु-संकटग्रस्त क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है और इन क्षेत्रों के लिए क्या विशेष हस्तक्षेप योजनाएं बनाई गई हैं; और

(ङ) क्या सरकार एक एकीकृत और जन-केंद्रित जलवायु अनुकूलन रणनीति सुनिश्चित करने के लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय कर रही है और यदि हां, तो ऐसे समन्वय तंत्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) सरकार अपने विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है, जिनमें राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) शामिल है। इस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, जल, संधारणीय कृषि, स्वास्थ्य, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, संधारणीय पर्यावास, हरित भारत तथा जलवायु परिवर्तन के लिए कार्यनीतिक ज्ञान जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में मिशन शामिल हैं। तमिलनाडु सहित छत्तीस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एनएपीसीसी के अनुरूप अपने राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एसएपीसीसी) तैयार की है, जिसमें राज्य-विशेष जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों को ध्यान में रखा गया है।"

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत कार्यनीतिक ज्ञान संबंधी राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसकेसीसी) के तहत तमिलनाडु राज्य जलवायु

परिवर्तन प्रकोष्ठ की स्थापना की है,जिसका उद्देश्य राज्य को संवेदनशीलता एवं जोखिम आकलन करने, मानव क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, जन जागरूकता कार्यक्रमों तथा संस्थागत क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने 'तटीय अवसंरचना पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव एवं अनुकूलन कार्यनीतियाँ' विषय पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास में उत्कृष्टता केंद्र को सहयोग दिया है। इस केंद्र द्वारा तटीय क्षेत्रों की जलवायु प्रणालियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने हेतु विभिन्न संख्यात्मक मॉडल विकसित किए गए हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय जलवायु-अनुकूल कृषि नवाचार (एनआईसीआरए) के अंतर्गत धर्मपुरी, विलुपुरम, कोयंबटूर, पेरम्बलूर और रामनाथपुरम जैसे कृषि जिलों के लिए जलवायु-के प्रति संवेदनशीलता के आकलन किए गए हैं।

तमिलनाडु राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (टीएनएसएपीसीसी) तथा टीएनएसएपीसीसी 2.0 (2022-2030) में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने, ऊर्जा दक्षता में सुधार करने तथा निम्न-कार्बन विकास को सहायता देने हेतु महत्वाकांक्षी उपायों का उल्लेख किया गया है। हरित तमिलनाडु मिशन का उद्देश्य व्यापक स्तर पर देशी प्रजातियों के वृक्षारोपण तथा संधारणीय गतिशीलता के माध्यम से कार्बन सिंक को सुदृढ़ करना है। अनुकूलन संबंधी प्रयास तटीय पुनर्स्थापन, मैंग्रोव एवं आर्द्रभूमि संरक्षण तथा जल-कुशल पद्धतियों के साथ जलवायु-अनुकूल कृषि के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र की अनुकूलन क्षमता बढ़ाने और संवेदनशील समुदायों को जलवायु-सुरक्षित बनाने पर केंद्रित हैं।

तमिलनाडु में जलवायु-अनुकूल कृषि, जल संसाधन प्रबंधन तथा तटीय संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष (एनएएफसीसी) के अंतर्गत वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। इस क्रम में मन्नार की खाड़ी, तूतीकोरिन, रामनाथपुरम, कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली तथा सलेम और विरुधुनगर जिलों के वर्षा-आधारित जलग्रहण क्षेत्रों में 48 करोड़ रुपये से अधिक लागत की परियोजनाओं को सहायता दिया गया है।

जल संसाधन प्रबंधन के संदर्भ में, भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने हेतु अनेक महत्वपूर्ण योजनाएँ लागू की जा रही हैं, जिनमें नमामि गंगे कार्यक्रम, राष्ट्रीय जल मिशन, जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्वच्छ भारत मिशन, बांध पुनर्वास एवं सुधार कार्यक्रम आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय भूजल बोर्ड ने तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन निगरानी नेटवर्क की स्थापना की है।

जलवायु अनुकूलता से संबंधित प्रयास विभिन्न मंत्रालयों, राज्य विभागों, अनुसंधान संस्थानों तथा स्थानीय निकायों के बीच समन्वय के साथ किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के अंतर्गत राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एसएपीसीसी) का ढांचा, तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी के विभिन्न मिशन (आर्द्रभूमि, तटीय पुनर्स्थापन, जलवायु परिवर्तन तथा हरित तमिलनाडु मिशन), जलवायु एवं स्वास्थ्य के एकीकरण हेतु राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनपीसीसीएचएच), तथा समुदाय-आधारित पहलें शामिल हैं। जन जागरूकता को राष्ट्रीय हरित कोर, सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) कार्यकलापों, इको-क्लब, हरित मित्र और हितधारक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है, जिससे सरकार-समग्र और जन-केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है।

****